

**Weekly unemployed allowance**

\*69. SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Will the Minister of SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP be pleased to state:

(a) whether, on the lines of other countries, of the world, Government is considering to provide weekly unemployment allowance to unemployed persons till they get employment; and

(b) if not, the reasons therefor?

THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (DR. MAHENDRA NATH PANDEY): (a) and (b) A statement is laid on the Table of the House.

**Statement**

(a) and (b) There is no such proposal to provide weekly unemployment allowance to unemployed persons. However, as per provision under Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), 2005, every State/Union Territory has to provide at least one hundred days of guaranteed wage employment in every financial year to every rural household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. The demand for work itself is influenced by various factors such as rain-fall pattern, availability of alternative and remunerative employment opportunities outside MGNREGA and prevailing unskilled wage rates.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA: Sir, is this true that in 2018, the estimated youth unemployment rate in India was at 10.42 per cent? According to the source, the data are of ILO estimates. For the past decade, India's youth unemployment rate has been hovering around the 10 percent mark, which, if true, would be the highest rate in 45 years.

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: सभापति महोदय, माननीय सांसद जी का जो मूल प्रश्न है, वह बेरोजगारी भत्ते से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हमने उसका उत्तर दे दिया है। जहां तक दर का सवाल है। पहले मैं माननीय सांसद जी और सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा विभाग रोजगार के लिए लोगों को कौशल प्रदान करके उन्हें तैयार करता है। उनको विभिन्न क्षेत्रों में कौशलकृत करके उन्हें रोजगार उपलब्ध हो, रोजगार के अवसर उपलब्ध हों और नियमित रोजगार और entrepreneurship के माध्यम से भी रोजगार प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इस पर बहुत ही सार्थक पहल की है। अभी माननीय मंत्री जी मनरेगा के संदर्भ में कह रहे थे, वह भी रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध करवाता है। श्रम मंत्रालय रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराता है, टैक्सटाइल मिनिस्ट्री भी रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है, तो रोजगार की दृष्टि से हमारी सरकार ने बहुत ही अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाए हैं।

श्री सभापति: आपका सेकेंड सप्लीमेंटरी पूछिए। आप skill से संबंधित ही प्रश्न पूछिए।

श्रीमती झरना दास बैद्य: सर, मैंने परसेंटेज के बारे में बोला है। Sir, is this true that 33 per cent of India's skilled youth are jobless?

MR. CHAIRMAN: Whether 33 per cent of the skilled youths are jobless, उसके बारे में सवाल पूछा गया है।

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: सर, इसके भिन्न-भिन्न आंकड़े हैं। मैंने आपको बताया है कि कौशलकृत करने के आंकड़े मेरे पास बिल्कुल सटीक उपलब्ध हैं, लेकिन यह जो विभिन्न सर्वे है कि कहीं कुछ परसेंटेज बताते हैं, जो unemployed हैं और कितना employment हमारी सरकार ने दिया, उसके बारे में भी आंकड़े हैं। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ कि मुद्रा योजना जो हमारी नई प्लैगशिप योजना है, उसमें एक करोड़ दस लाख लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार उपलब्ध कराया है। ऐसे अनेक रोजगार उपलब्ध कराए हैं और उस दिशा में और पहल की जाएगी।

श्री राकेश सिन्हा: सभापति महोदय, कौशल विकास योजना के अंतर्गत अच्छा कार्य हो रहा है, उसके लिए मैं मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूँ। सर, मेरा आपके माध्यम से एक प्रश्न यह है कि क्या सरकार जिन लोगों का यह skill develop कर रही है, तो क्या उनकी placement के लिए कोई योजना बना रही है कि निजी क्षेत्र और पब्लिक सेक्टर, दोनों में उनकी placement हो सके, जैसा कि इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों placement होता है। क्योंकि उसके नहीं करने के कारण, जिन बच्चों को skill में develop किया जाता है, वे employment के लिए भटकते रहते हैं। उन्हें जानकारी नहीं होती है कि उनके skill के हिसाब से रोजगार कहाँ मिलेगा? मैं यह मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय: हम लोग इनके placement के साथ ही रोजगार के दो-तीन components देते हैं, चाहें प्रधानमंत्री कौशल केंद्र हो, जो पहले 600 से थोड़े ज्यादा थे और आज बढ़कर 812 हैं या तमाम एनजीओज, training partners को देते हैं। हम उनके साथ कंडीशन लगाते हैं कि आप उनको इतना रोजगार, 50 परसेंट उपलब्ध कराएंगे, तभी हम आपकी लिस्ट किस्त देंगे। उस आधार पर placement के जो हमारे पास लगभग पिछले तीन-चार वर्षों के आंकड़े हैं, उनमें अन्य मंत्रालयों के आंकड़ों की डिटेल् में जानकारी के अनुसार माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। मेरे विभाग के आंकड़े हैं कि 69 लाख को हमने RPL-plus-PMKVY और इन सबके द्वारा train किया है, यह पूरी तरह अधिसूचित है। उसमें particularly प्रधान मंत्री कौशल योजना के अंतर्गत हमने 12 लाख के ऊपर रोजगार इसके माध्यम से उपलब्ध कराए हैं।

डा. अशोक बाजपेयी: माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से माननीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि आज देश में दो Defence Production Corridor बन रहे हैं और defence production के क्षेत्र में बहुत सारे foreign investors देश में आ रहे हैं। वैसे भी देश से import के लिए defence production की काफी संभावनाएं हैं। माननीय मंत्री जी, इसको ध्यान में रखते हुए इस देश में defence production के क्षेत्र में कौशल विकास की कोई विशेष योजना परिचालित करके, बड़ी संख्या में defence production के लिए skilled people तैयार करने के कार्य की क्या कोई कार्य योजना है? यदि है, तो उसके बारे में बताएं।

डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: माननीय सदस्य का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन defence देश का एक बहुत महत्वपूर्ण और एक अति प्राथमिकता का विषय है। अब तक 38 Sector Skill Councils हमारे विभाग के through हैं, जो NSDC और हमारा डिपार्टमेंट और काउन्सिल्स मिलकर ये job roles फिक्स करते हैं। हम लोग आपकी इस बात को बड़ी गंभीरता प्रदान कर रहे हैं और हमने हाल में defence के क्षेत्र में भी कौशलीकृत करने के लिए हमने एक नया MoU किया हुआ है।